

झारखंड कैबिनेट के महत्त्वपूर्ण नरिणय

चर्चा में क्यो

19 जनवरी, 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य के 136 आवासीय वदियालयों के कक्षा-1 से 12 तक के 21 हजार छात्रों को मोबाइल टैब देने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के साथ ही कुल 51 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

प्रमुख बदि

- झारखंड कैबिनेट ने वत्तीय वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पछिड़ा वर्ग कल्याण वभिग के अंतर्गत कुल 136 आवासीय वदियालयों में कक्षा-1 से 12 तक के वदियार्थियों को मोबाइल टैब देने का नरिणय लया है। इस क्रम में 21 हजार छात्रों को यह सुवधि दी जाएगी।
- कोविड-19 के क्रम में आवासीय वदियालय बंद रहने के कारण घर पर रहकर पठन-पाठन जारी रखने के लिए ये मोबाइल टैब काम आएंगे। कैबिनेट ने लगभग 26.25 करोड़ रुपये के लागात वाले इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।
- राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी का प्रसार हो, इसके लिये सरकारी स्कूलों की पहली से बारहवीं कक्षा तक के छात्रों के नोटबुक के पहले पन्ने पर सरकार की योजनाओं की जानकारी भी अंकित कराई जाएगी।
- कैबिनेट ने एक अन्य महत्त्वपूर्ण फैसला लेते हुए पारा शक्तिषकों से जुड़े झारखंड सहायक अध्यापक शक्तिषक सेवा नयिमावली को भी मंजूरी दे दी। पारा शक्तिषक अब सहायक अध्यापक कहे जाएंगे। इस नयिमावली के तहत 62878 पारा शक्तिषकों की सेवा 60 साल तक नरिधारित की गई है। नयिमति अंतराल पर परीक्षा आयोजित कर योग्यता के आधार पर मानदेय वृद्धि, अनुकंपा समेत अन्य लाभ दिए जाएंगे।
- कैबिनेट ने फैसला लया है कि केंद्र प्रयोजित पोषाहार योजना में 6 से 36 माह के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, कुपोषित बच्चों को टेक होम योजना के तहत अब सामान्य चावल की बजाय फॉर्टिफाइड चावल का वतिरण कया जाएगा।
- कई वभिगों की सेवा बहाली संबंधी नयिमावली में भी परिवर्तन को मंजूरी दी गई है। वहीं कारखानों में काम करने के दौरान सलिकोसिस बीमारी से ग्रसित होने पर एक लाख व मौत होने पर आश्रति को चार लाख रुपए की राशि दी जाएगी।
- आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारियों की सेवानवृत्त की उमरसीमा 60 से बढ़ाकर 65 साल की गई है।
- राज्य के सभी पंचायत भवन, नगर नकियों, वार्ड में आधार का परमानेंट इनरॉलमेंट सेंटर खुलेगा। राज्य सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी व ई गवर्नेंस वभिग ने इसके लिए सीएससीएसपीवी के साथ एमओयू को मंजूरी दी है।
- राज्य भर में भू-अभिलेखों की सुरक्षा के लिये आईटी एडवाइजरी सर्विस के तहत एनआईएसजी नाम की एजेंसी का चयन मनोनयन के आधार पर कया गया है।
- राज्य में शराब के राजस्व में बढ़ोतरी के लिए छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लमिटेड के साथ राज्य सरकार एमओयू करेगी। राज्य के ब्रविरेज कॉर्पोरेशन के परामर्शी के तौर पर छत्तीसगढ़ की सरकारी एजेंसी का चयन कया गया है।
- अन्य प्रमुख योजनाओं को मली मंजूरी-
 - नंदनी जलाशय योजना के तहत मुख्य नहरों के अवशेष व पुनरुदवार पर 56 करोड़ 7 लाख 64 हजार रुपए के खर्च को मंजूरी।
 - कांची सचिई परियोजना के पुनरुदवार के लिए 29 करोड़ 23 लाख 37 हजार रुपए की स्वीकृति।
 - आईटीआईएफ 27 के तहत 17 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के लिए नाबार्ड से 185 करोड़ रुपए कर्ज़ लेने की मंजूरी।
 - टोकथि ओलंपिक में झारखंड से भारतीय हॉकी टीम में खेल रही नकिकी प्रधान, सलमि टेटे के पुरस्कार राशि की घटनोत्तर स्वीकृति, तीरंदाज़ दीपिका कुमारी, कोमोलिका बारी, अंकिता भगत व प्रशक्तिषक पूर्णामि महतो को दी गई ईनाम राशि की घटनोत्तर स्वीकृति।
 - एक से तीन साल के बच्चों के फाउंडेशन लटिरेसी कार्यक्रम के लिए केंयर इंडिया संस्था का मनोनयन।
 - गोडनन में पुलसिकर्मियों के लिए 58 करोड़ 1 लाख 80 हजार रुपए खर्च कर आवासीय कॉलोनी के नरिमाण को मंजूरी।
 - वधियक योजना के अंतर्गत वधियकों की अनुशंसा पर जलापूर्ति योजनाओं के लिये 50 लाख रुपए के खर्च को ऐच्छिक कया गया है।
 - दुमका में मसलिया- राजेश्वर सचिई परियोजना के तहत भूमिगत सचिई पाइपलाइन लगाने में 1204 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी।

